SHRI V.N. GADGIL : It is purely a law and order question which the State Government is handling. How do we come in ? It is not a dispute between management and the employees.

MR. SPEAKER : Yes, why should you come in ?

श्री जगपाल सिंह : आपको जांच करानी चाहिये । क्यों नहीं जांच कराई ? सैकड़ों लोग जेल में डाल दिये गये । तो क्या आप जांच करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री जगपाल सिंह : क्यों नहीं करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : स्टेट असेम्बली वहां है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, क्या वहां के अधिकारियों की मर्जी के बगैर···

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : That has nothing to do with the main question here. I am not allowing. Law and order is their subject. Yes, Mr. Ajit Kumar Mehta.

श्री जगपाल सिंह : आप अलाऊ करें या न करें···

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : No names are allowed here.

श्री जगपाल सिंह : इस पर आप इंक्वायरी कराइये ।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप पढ़ कर आया करें ।

PROF. K.K. TEWARY : You should ask him to take back the names. (*Interruptions*) He should be expelled. (*Interruptions*)

SHRI JAGPAL SINGH :.........*

MR. SPEAKER : This is not on record. Whatever this gentleman is saying is not going on record.

श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े मामले

*686. **श्री प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम न्यायालयों और न्यायधिकरणों में बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें शीघ्र ही निपटाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक निश्चित अवधि में उक्त मामलों को निपटाने के अनुदेश भी जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे मामलों का यथा समय निपटारा करने हेतु इन न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

*Not recorded.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION : (SHRI DHARMAVIR) : (a) The total number of industrial disputes pending in the Central Government Labour Courts/ Industrial Tribunals as on 28.2.1983 was 8150. According to the information available with us from the State Governments similar pendency in the States as on 1.11.1981 amounted to 47,466 industrial disputes.

(b) Necessary amendments have been made in the Industrial Disputes Act to ensure time bound disposal of adjudication cases. Steps have also been taken to review the procedure for the disposal of such cases.

(c) and (d) : The Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts have been asked to dispose of a prescribed minimum number of cases every month. The matter was also discussed in the State Labour Ministers' Conference held in September, 1982 and the State Governments have been asked to expedite the disposal of cases pending in their Courts.

(e) and (f) The Central Government has set up a new Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Chandigarh. According to the information available with us, the State Governments of Assam, Madhya Pradesh, Haryana, Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh and the Union Territory of Delhi have also set up additional Labour Courts/Industrial Tribunals recently.

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, यदि आप जवाब को देखें तो केन्द्रीय सरकार, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों में 28-2-83 को 8150 कैसेज़ का विवरण दिया गया है। लेकिन राज्यों में विवरण दिया गया है 1-11-1981 तक का। समझ में नहीं आता डेढ़ साल पुराना विवरण देने का यहां क्या उपयोग था? उस पर भी डेड़ साल पहले 47,466 कैसेज पेंडिंग थे। तो टोटल मिला करके उसके हिसाब से 55,500 होते हैं। और ऐग्जक्ट फिगर दें तो पता नहीं कितने होंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लम्बित मुकदमें हैं इनके क्या यहीं तीन कारण हैं? पहला यह कि न्यायमूर्तियां की कमी, न्यायालयों की कमी जिसके कारण मुकदमें लंबित रहते है, उनका शीघ्र निपटान नहीं होता है, इसलिये लिस्ट बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ नये मुकदमें आने लगे हैं। ऐसे मामलों के निपटाने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं?

आपने कहा है कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों व श्रम-न्यायालयो से कहा गया है कि वे प्रत्येक मास में निर्धारित न्यूनतम संख्या में मामलों को निपटाएं। आपके यह आदेश कब ज़ारी हुए और इसके अभी तक क्या ठोस परिणाम निकले हैं? कितने मुकदमें इस आदेश के बाद निपटाये जा चुके हैं? इसके साथ ही यह भी बतायें कि लंबित मुकदमें कितने हाई-कोर्ट में हैं और कितने सुप्रीम कोर्ट में हैं और कितनों में स्टे आर्डर है?

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल कीजिये, 50 सवाल क्यों करते हैं? आप अपने सवाल का अपने आप सत्यानाश कर लेते हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल हमने स्टेट में पेंडिंग मुकदमों की 1-11-81 तक की जानकारी दी है। हमारे पास स्टेट्स से जो इन्फार्मेशन आती है, उसको कम्पाइल करके हम इन्फार्मेशन देते हैं। हमारे पास स्टेट्स से लेटेस्ट इन्फार्मेशन नहीं आई है। हम स्टेट्स को पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं लेकिन कुछ स्टेट्स इन्फार्मेशन देती हैं. कुछ नहीं देती हैं। कुछ स्टेट्स रिमाइन्डर के बाद भी जवाब नहीं देती हैं। जब इन्फार्मेशन नहीं आती है तो उसको कम्पाइल करके अप-टू-डेट इन्फार्मेशन देना मुश्किल हो जाता है।

हमारे श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की इन्फार्मेशन हमारे पास मिलती है, क्योंकि वह इन्फार्मेशन कलैक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है। उसका हमने लेटेस्ट आपको बताया है। माननीय सदस्य मालूम करना चाहते थे कि जल्दी केसेज़ को डिस्पोज़ आफ करने के बारे में हमने क्या कार्यवाही की है ? उसके लिये मैंने जवाब में बताया कि उसके अलावा हमने लेबर मिनिस्टर्स की कान्फरेंस बुलाई थी···

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने जानना चाहा कि उसका क्या ठोस परिणाम निकला ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सितम्बर, 1982 में लेबर मिनिस्टर्स की कान्फरेंस में मैंने कहा कि पैंडेंसी बहुत पड़ी हुई है, इसका डिस्पोजल अच्छी तरह से करना चाहिये, इसके लिये आपको प्रोसीजर स्ट्रीम-लाइन करना पड़ेगा और लेबर कोर्ट व ट्रिबयूनल को भी आपको सैट-अप करना होगा।

नतीजे के तौर पर मेरे पास फिगर्स हैं। अगर मैं इन सब को पढ़ता जाऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं समझता हूं कि हर स्टेट में ट्रिबयूनल और लेबर-कोर्ट बहुत हैं। सितम्बर, 1982 के बाद जो निर्णय लिया उसके मुताबिक आन्ध्र प्रदेश में 2 लेबर-कोर्ट सैट-अप करने का काम किया और असम में एक ट्रिब्यूनल सैट अप हो चुका है। इस तरह से मेरे पास सारी जानकारी है। माननीय सदस्य चाहें तो मैं सबको सप्लाई करने के लिये तैयार हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने मामले पैंडिंग हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह भी आपको भेज देंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : पहले स्टे-आर्डर करवा लेते हैं, फिर क्वैश्चन करवाते हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने केसिज़ पैंडिंग हैं। लेकिन अपने मूल सवाल में उन्होंने पूछा है कि लेवर कोर्ट्स और लेवर ट्रिब्यूनल्ज़ में कितने केसिज़ पैंडिंग हैं। इंडस्ट्रियल डिसपूट्स एक्ठ के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसिज़ पैंडिंग नहीं होते हैं। कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर स्टे आर्डर ले सकती है, लेकिन ऐसे केसिज़ बहुत कम हैं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, श्रमिक सम्बन्धी मुकदमों के ऊपर सांविधानिक मुकदमों को प्राथमिकता मिलने के कारण लंबित श्रमिक मुकदमों की सूची बहुत लंबी हो जाती है तथा उन मुकदमों की उपादेयता खत्म हो जाती है। एक केस के बारे में मैं जानता हूं कि एक आदमी 17 साल से मुकदमा लड़ रहा है, मगर अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। इस तरह इन मुकदमों की उपादेयता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। न्यायालयों पर श्रमिक सम्बन्धी मुकदमों के अलावा अन्य मुकदमों का अत्यधिक भार रहने के कारण ट्रेड यूनियनों ने श्रमिक मुकदमों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सैपेरेट लेबर बैंच की स्थापना की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सैंट्रल सैक्टर में ये जो कोर्ट्स हैं, ये सब इंडस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट्स हैं। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस कोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। जो कुछ मैं

कह रहा हूं, वह सब लेबर कोर्ट्स के बारे में कह रहा हूं ।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैंने पूछा है कि ट्रेड यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अतिरिक्त लेबर बैंच की जो मांग की है, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने बैंच पर बैठिए ।

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : Even in most of the limited number of labour courts and tribunals, there is no judge at all. Even in the Delhi Labour Court there is no Presiding Officer for the last one year and so many cases are pending there. Even after 5-6 years these cases are going on like this and you know justice delayed is justice denied. So, this is what is happening. Now most of the governments are not referring cases for adjudication and to avoid these things, the services of the persons who are victimised are terminated. There is so way out for justice, no remedy. What is the proposal by the Minister to have a speedy trial and also to create more facilities for the people to get justice ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : We want more judges to be appointed, that is the only remedy...(*Interruptions*)

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : What about the Delhi Labour Tribunal... (*Interruptions*)

SHRI VEERENDRA PATIL : Sir, I have already made it clear that the pendency is large and it is necessary and we have insisted upon the Labour Ministers in the Labour Ministers' Conference which was held in the month of September, 1982, that they should see that more tribunals and more labour courts are appointed. Sometimes the parties themselves are responsible for the delay in the disposal of cases which have in the Labour Courts and the Tribunals because every time they come and ask for adjournment. When they ask for adjournment, it becomes difficult. We had discussion in the month of October, 1981 with all the Presiding Officers of the Labour Courts and Tribunals, so far as Central Industrial Tribunals-cum-Labour Courts are concerned. The meeting was held here in Delhi and we had detailed discussions and a norm was fixed that they should dispose of at least six cases in a month. Recently in the Industrial Disputes Act also we have made an amendment fixing the time limit for individual disputes as three months and for collective disputes we have provided the limit to be fixed at the time of making a reference. We have made all attempt to start more and more industrial tribunals.

MR. SPEAKER : What about Tribunals without Judges ?

SHRI VEERENDRA PATIL : There was some difficulty in finding suitable presiding officers. So far as the Tribunals and Labour Courts in the Central sphere are concerned, the appointments are made by the Central Government. We have got only 9 industrial-cum-labour courts and to all these 9 we have appointed presiding officers. There is no vacancy. So far as the Tribunals and labour courts in the States are concerned, the appointment is the responsibility of the State Government concerned. If there is any difficulty for the States in appointing Judges, or if the Hon. Members have got any instances where the Tribunal or Labour Court has no Presiding Officer, if it is brought to our notice, we will take it up with the respective State Government.

SHRI M.M. LAWRENCE : This is a serious problem affecting millions of workers. The Hon. Minister in his reply has stated that the number of industrial disputes pending in the Central sphere was 8,150 and in the State sphere 47,466. These dispute concern the working conditions of millions of workers. Besides that, there are millions of workers, who are outside the industries and factories. Since the non-disposal of these cases increases the sufferings of the workers

and since the reply of the Government indicates that they are not very serious in this matter, I want to know how many workers are involved ?

SHRI VEERENDRA PATIL : The Hon. Member wants to know how many millions of workers are involved. I have to collect the information from the State Government.

Pension and Gratuity for Extra Departmental Staff Working in P & T Department

*687. SHRI AJOY BISWAS : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) total number of extra departmental staff working in the P & T Department;

(b) whether Government have any proposal to bring them in the scheme of pension, gratuity, etc; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL) : (a) Total number of E.D. Staff as on 31.3.82 is 2,92,526.

(b) No, Sir. They are however eligible for ex-gratia gratuity after 15 years of satisfactory service.

(c) The Extra-departmental Agents are not regular employees of the Department and are only part-time Agents. They are not covered under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. They get remunerations in accordance with their duty hours.

SHRI AJOY BISWAS : It is really a serious matter that out of the total strength of 8 lakhs of employees of the P & T, nearly 3 lakhs are ED staff. Earlier, the strength of the ED staff was only 20,000. Now it has increased to 3 lakhs. This system was introduced by the British and we are following that. Instead of becoming model employers, we have become model exploiters. Here I want to draw the attention of the Minister to a letter written by the then Minister, Shri A.P. Sharma, dated 16.1 75, to the late Shri A.K. Gopalan, where he stated that a case is pending in the Supreme Court whether the ED staff could be regarded as regular civil servants or not. The Supreme Court gave the judgment on 22.4.77, declaring the ED staff as holders of civil posts. They are clearly regular employees of the department. Will the Hon. Minister appoint a House Committee, or some other Committee, to go into the manifold aspects of the judgment of the Supreme Court in order to decide the question of pro rata wages dearness allowance, pension, gratuity and other benefits as are eligible to the corresponding categories of regular P & T staff ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI V.N. GADGIL) : Sir, the Supreme Court Judgment holding that they are the holders of civil posts is only in respect of Article 311 and the advice to us is that this Judgment does not amount to saying that they are full-time Government servants.

As far as the suggestion of the Committee is concerned, this matter is already inquired into by the Petitions Committee of the Rajya Sabha and most of the recommendations of that Committee have already been accepted.

SHRI AJOY BISWAS : Sir, he has referred to the recommendations of the Petitions Committee of the Rajya Sabha, but they have not implemented all the recommendations; most of the recommendations are not implemented. Their main recommendations are :

"(i) The Department should consider raising the present rates of allowances paid to the EDAs and also